लीला गुप्ता एवं अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 5564 वर्ष 2005)

31 अगस्त, 2010

(आफताब आलम और आर.एम. लौढा जे.जे.)

मोटर वाहन अधिनियम, 1939 धारा 110 ए-घातक दुर्घटना- दावा याचिका- न्यायाधिकरण द्वारा मुआवजे का अवार्ड- 16 के गुणक का उपयोग करके उच्च न्यायालय द्वारा संवर्धित-उच्च न्यायालय मुआवजे की राशि तक पहुँचने के बाद एक तिहाई की कटौती जीवन की अभैद्यता और अनिश्चितता की और की -अपील में अवधारित: उच्च न्यायालय द्वारा गुणक का प्रमाणन सुसम्मा थॉमस मामले के दिशानिर्देश अनुसार सही है, हालांकि, 16 के गुणक पर गुणक का पूंजीकरण उच्च पक्ष पर है- इसलिए, गुणक को घटाकर 14 कर दिया गया-मुआवजे की एक तिहाई हिस्से की कमी जीवन की अभैद्यता और अनिश्चितता की ओर सही नही है-एक बार जब गुणक और गुणक का पता चल जाता है, अनिश्चितताओं और अन्य आकस्मिकताओं के लिए आगे की कोई कटौती करने की आवश्यकता नही है।

एक मोटर दुर्घटना में 39 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी और तीन बच्चों (अपीलकर्ताओं) ने एक दावा याचिका धारा 110 ए. मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत दायर की। दावा न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि दावेदार रूपये 2,61,800/- बकाया राशि के साथ मुआवजे और उस पर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से भविष्य का ब्याज की राशि के हकदार है। अपील में, मृतक की वार्षिक आय की गणना करने के बाद न्यायालय ने 16 का गुणक लागू किया और रू. 6,91,200/- मुआवजा निर्धारित किया गया। जीवन की अभेद्यता और अनिश्चितता को देखते हुए, मुआवजे के लिए पहुंचाई गई राशि को एक तिहाई कम कर दावेदारों को रू. 4,70,000/- दिलाया गया था। अपील में विचार के लिए प्रश्न 16 के गुणक के साथ पूंजीकृत गुणक का पता लगाने के बाद) मूल्यांकन किये गये मुआवजे को 1/3 से कम करने के उच्च न्यायालय के निर्णय की शुद्धता के संबंध में था।

न्यायालय द्वारा आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया गया :-

1.1 क्षतिपूर्ति देने का उद्देश्य है- मृतक के आश्रितों को, जो परिवार के अन्नदाता थे, आर्थिक रूप से उसी स्थिति में लाने जैसा मानों उन्होने अपना स्वाभाविक जीवन जिया हो । यह दावेदारों को बेहतर वित्तीय स्थिति में रखने के लिए नही बनाया गया है। जिसमें वे अन्यथा होते, यदि

दुर्घटना नही हुई होती। साथ ही, मुआवजे का निर्धारण एक सटीक विज्ञान नही है और अभ्यास में अनुमान और अनुमानों के आधार पर मूल्यांकन शामिल है। अभेद्य कारक और अप्रत्याशित आकस्मिकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम 1939 की धारा 110 बी (अब मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 168) में न्यायसंगत क्षतिपूर्ति का अवार्ड अधिनियमित है। (पैरा 3)

1.2 सुसम्मा थामस मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने गुणक का निर्धारण या आश्रितता की राशि 3600/- प्रतिमाह निर्धारित की। उच्च न्यायालय ने गुणक राशि का पता लगाने में सुसम्मा मामले के निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखा है जिसमें पुनःविचार की आवश्यकता नही है। सरला वर्मा मामले में बताए गए दिशानिर्देशों को लागू करके संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षैत्र में इस दूरी पर गुणक की पुनःगणना न तो उचित है और न ही वांछनीय है। हालांकि, 16 के गुणक पर गुणक का पूंजीकरण उच्च पक्ष पर है और 14 का गुणक, तत्काल मामले के तथ्यों में, न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। (पैरा 8)

1.3 उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारण के बाद मूल्यांकन किए गए मुआवजे का 1/3 भाग कटौती करने में गलती की थी। एक विशेष गुणक पर पूंजीकृत गुणक का निर्धारण की विधि भविष्य की आकस्मिकता,

नुकसान का आंकलन अभैद्यता के कई कारको को ध्यान में रखती है। एक बार गुणक और गुणक का निर्धारण किया जाता है तो अनिश्चितताओं और अन्य आकस्मिकताओं की दोनों ओर आगे कोई कटौती करने की आवश्यकता नही है। (पैरा 9)

1.4 उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया मुआवजा की राशि रू. 4,70,000/- को 6,04,800/- रू. तक बढ़ाया जाता है। जो उचित और न्यायसंगत है। अपीलार्थी दावा याचिका दायर करने की तारीख से उसके वास्तविक भुगतान की तारीख तक बढ़ी हुई राशि पर प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत साधारण दर से ब्याज का भी हकदार होगा। (पैरा 9)

महाप्रबंधक, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम, त्रिवेंद्रम बनाम सुसम्मा थॉमस (श्रीमती) और अन्य। (1994) 2 एस.सी.सी. 176-पर विश्वास किया ।

सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य । (2009) 6 एस.सी.सी. 121-लागू नही होना अवधारित किया।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम व अन्य बनाम त्रिलोकचंद्रा और अन्य। (1996) 4 एस.सी.सी. 362; अबाती बेजबरूआ बनाम भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेसक्षण (2003) 2 एस.सी.सी. 148; फकिरप्पा और अन्य बनाम कर्नाटक सीमेंट पाइप कारखाना और अन्य। (2004) 2 एस.सी.सी.

473; टी.एन. राज्य परिवहन निगम लिमिटेड बनाम एस.राजप्रियाज और अन्य। (2005) 6 एस.सी.सी. 236 य न्यू इंडिया बीमा कम्पनी लिमिटेड बनाम चार्ली और अन्य (2005) 10 एस.सी.सी. 720; यू.पी. स्टेट रोड परिवहन निगम बनाम कृष्णबाला और अन्य। (2006) 6 एस.सी.सी. 249; ओरियंटल बीमा कम्पनी लिमिटेड बनाम मीना वरियाल और अन्य। (2007) 5 एस.सी.सी. 428; रेशमा कुमारी और अन्य बनाम मदन मोहन और अन्य। (2009) 13 एस.सी.सी. 422-संदर्भित।

टैफ वेले रेलवे कं. बनाम जेनकिंस (1913) एसी 1; डेविस और अन्य बनाम पॉवेल डफरिन एसोसिएटेड कोलियरीज लिमिटेड (1942) 1 ऑल ई. आर. 657 य नैन्स बनाम ब्रिटिश कोलंबिया इलेक्ट्रिक रेल्वे कं. लिमिटेड (1951) 2 ऑल ई.आर. 448-संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

(1994) 2 एससीसी 176	संदर्भित किया	पैरा 4
(1996) 4 एससीसी 362	संदर्भित किया	पैरा 5
(2009) 6 एससीसी 121	अप्रयोज्य माना	पैरा 6
(2009) 13 एससीसी 422	संदर्भित किया	पैरा 6
(2003) 2 एससीसी 148	संदर्भित किया	पैरा 6

(2004) 2 एससीसी 447 संदर्भित किया पैरा 6

(2005) 6 एससीसी 236 संदर्भित किया पैरा 6

(2005) 10 एससीसी 720 संदर्भित किया पैरा 6

(2006) 6 एससीसी 249 संदर्भित किया पैरा 6

(2007) 5 एससीसी 428 संदर्भित किया पैरा 6

(1942) 1 ऑल ई.आर. 657 संदर्भित किया पैरा 6

सिविल अपीलीय क्षैत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5564/2005.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, न्यायपालिका के एफ.ए.एफ.ओ.सं. 385/1987 मे पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 3.9.2003 से ।

अपीलार्थी के लिए टी. महिपाल।

टी.एन.सिंह, शेखर राज शर्मा, चन्द्र प्रकाश पांडे उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायधीश आर.एम. लौढा जे. द्वारा सुनाया गया :-

1. गंगा प्रसाद गुप्ता- मृतक, प्रथम अपीलार्थी का पति और द्वितीय, तृतीय और चोथे अपीलार्थी का पिता 8 जुलाई, 1985 की एक मोटर दुर्घटना में मृत्यु हुई। उस समय उनकी आयु 39 वर्ष थी और वे उत्तर

प्रदेश राज्य के सिंचाई विभाग में कार्यवाहक कार्यकारी अभियंता के पद पर कार्यरत थे। यदि वह जीवित रहते, उन्हें सेवानिवृति की आयु (यानी 58 वर्ष) तक पहुँचनेमें लगभग 18 वर्ष लगते। सेवानिवृति के बाद उन्हें पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त होती। उनकी पत्नी व तीन बच्चों ने मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 110 ए. के तहत उत्तरदाताओं के खिलाफ दावा याचिका दायर की। मोटर दुर्घटना अधिनियम, 1939 (संक्षेप में, श्1939 अधिनियमश्) में 7,00,000 रूपये मुआवजे का दावा प्रत्यर्थियों के खिलाफ दावा न्यायाधिकरण, मिर्जापुर (संक्षेप में न्यायाधिकरण) में पेश किया। दुर्घटना की तारीख पर उनका सकल वेतन रू. 2,680/- प्रति महीना था। न्यायाधिकरण ने माना कि मृतक ने परिवार में योगदान किया होगा, रू. 2,200/- प्रतिमाह (रू. 26,400/- प्रतिवर्ष) और 18 के गुणक को लागू करके, यह निष्कर्ष निकाला गया कि विधवा और बच्चों को आर्थिक क्षति रू. 4,75,200/- अपनी सेवानिवृति की आयु तक होगी। न्यायाधिकरण ने तब 1/3 की कटौती, एकमुश्त भुगतान की जा रही राशि पर विचार करते हुए, अनिश्चितता और रूपये की राशि को आगे घटाकर की। 40,000/- समूह बीमा योजना के लिए, मुआवजे का आंकलन 2,76,800/- रूपये की सीमा तक किया , 15,000/- दावेदारों को बिना दोष दैयता पहले से ही भुगतान किया जा चुका है, न्यायाधिकरण ने 24 फरवरी, 1987 के अपने निर्णय में कहा कि दावेदार 2,61,800/- रूपये की राशि के हकदार है और उत्तरदाताओं को विचाराधीन राशि और उस पर भविष्य के ब्याज 9 प्रतिशत

प्रतिवर्ष के साथ उक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

2. दावेदारों की अपील पर, उच्च न्यायालय ने कहा कि दावेदार 4,70,000/- मुआवजे के रूप में प्राप्ति के हकदार थे तथा उस तारीख से प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ वास्तविक भुगतान किए जाने तक ब्याज प्राप्ति के हकदार है। उच्च न्यायालय ने मामले पर इस प्रकार विचार किया:

> ".....मृतक की आय रू. 2,700/- प्रतिमाह। यदि मृतक जीवित रहता तो 2700 ग् 2 त्र 5400 सुरक्षित रूप से माने जा सकते है। अब मृतक द्वारा स्वयं पर खर्च होने वाली राशि व्यक्तिगत खर्च 1/3 कम करने पर यह हमें 3600/- रूपये प्रतिमाह का आंकड़ा देता है। दावेदार का 3,600 ग् 12 त्र 43,200/- प्रतिवर्ष अपने परिवार के प्रति योगदान के रूप में आता है, मृतक की आयु को ध्यान में रखते हुए 43,200 को 16 से गुणा करने पर रू. 6,91,200/- आता है, हालांकि, जीवन की अभेद्यता और अनिश्चितता को देखते हुए, यह राशि 1-3 से कम हो जाती है। यह रूपये 4,70,000/- (राउंडिंग पर) का आंकड़ा देता है।"

3. एक सदी से अधिक समय से इंग्लेंड में पारंपरिक दृष्टिकोण यह

कायम रहा कि नुकसान का आंकलन इस आधार पर किया जाना है कि एक अवार्ड का मूल उद्देश्य चोटों के लिए वादी को यथासंभव पूर्ण मुआवजा लगभग प्रदान करना है। साथ ही इस नियम को घातक दुर्घटना कार्यो में स्वीकार किया गया है। टाफ वेल रेल्वे कम्पनी बनाम जेनकिन्स [1913] AC 1; में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अवधारित किया कि घातक दुर्घटना में मुआवजे का अवार्ड मृतक के आश्रितो को वह देना है, जो मृतक का परिवार युक्तियुक्त अनुमानित करें। परिवार के अन्नदाता आर्थिक रूप से उसी स्थिति में हो जैसे कि उन्होने अपनी प्राकृतिक जीवन अवधि जी ली हो। यह दावेदार को एक बेहतर वित्तीय स्थिति में रखने के लिए डिजाइन नही किया गया है जिसमें वे अन्यथा दुर्घटना के मामले में होते। मुआवजे का निर्धारण एक सटीक विज्ञान नही है और यहां अनुमान और अनुमानों के आधार पर एक मूल्यांकन अभ्यास में शामिल है और वहां कई अभेद्य कारक और अत्याशित है। आकस्मिकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। 1939 के अधिनियम की धारा 110-बी. में अधिनियमित वैधानिक नियम (अब धारा 168) मोटर वाहन अधिनियम, 1988) का अवार्ड मात्र क्षतिपूर्ति हैं ।

4. महाप्रबन्धक, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम, त्रिवेंद्रम बनाम सुसम्मा थॉमस (श्रीमती) और अन्य (1994) 2 एस सी सी 176. इस न्यायालय ने बड़े पैमाने पर अंग्रेजी निर्णयों पर विचार किया। साथ ही इस

हन्यायालय के पिछले निर्णयों और विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों में यह निर्धारित किया गया है कि गुणक विधि तार्किक रूप से सुदृढ़ और कानूनी रूप से अच्छी तरह स्थापित है और इसका पालन किया जाना चाहिए, जिससे विचलन केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही उचित ठहराया जा सकता है और बहुत असाधारण मामले. रिपोर्ट के पैरा 13 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

> "13. गुणक विधि में मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्भरता या गुणक के नुकसान का पता लगाना और उचित गुणक को पूंजीकृत करना शामिल है। गुणक का चुनाव मृतक की उम्र (या दावेदारों की उम्र, जो भी अधिक हो) द्वारा निर्धारित किया जाता है और यह गणना करके कि स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए उचित ब्याज दर पर निवेश किए जाने पर कौन सी पूंजी राशि, गुणक प्राप्त करेगी, वार्षिक ब्याज के माध्यम से। इस बात का पता लगाने में, इस तथ्य पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अंततः पूंजीगत राशि का उपभोग भी उसी अवधि में किया जाना चाहिए जिसके लिए निर्भरता बनी रहने की उम्मीद है।"

पैरा 17 में आगे कहा गयाः

> "17. गुणक वर्षों की खरीद की संख्या को दर्शाता है जिस

पर निर्भरता की हानि का पूंजीकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए ऐसे मामले को लीजिए जहां निर्भरता की वार्षिक हानि रु. 10,000. यदि 1,00,000 रुपये की राशि 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर निवेश की जाती है, तो ब्याज हमेशा के लिए निर्भरता का ख्याल रखेगा। इस मामले में गुणक 10 पर काम करता है। यदि ब्याज की दर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष है और 10 प्रतिशत नहीं है तो वार्षिक निर्भरता के नुकसान को रुपये में भुनाने के लिए गुणक की आवश्यकता होती है। 10,000 गुणक 20 होगा। फिर गुणक, यानी, 20 की वर्षों की खरीद की संख्या स्थायी रूप से वार्षिक निर्भरता प्राप्त करेगी। फिर गुणक को कम करने के लिए भविष्य की अनिश्चितताओं, तत्काल एकमुश्त भुगतान के लिए भत्ते, जिस अवधि पर निर्भरता कम रहेगी और पूंजी फ़ीड को ध्यान में रखना होगा इसके अलावा निर्भरता की अवधि के दौरान भी खर्च किया जाना चाहिए आदि। आमतौर पर अंग्रेजी न्यायालयों में ऑपरेटिव गुणक शायद ही कभी अधिकतम 16 से अधिक होता है। जैसे-जैसे मृत व्यक्ति (या आश्रितों की उम्र, जो भी अधिक हो) की उम्र बढ़ने के साथ इसमें कमी आएगी।"

गुणक के पहलू से निपटते समय, न्यायालय ने कहा कि गुणक के निर्धारण में भविष्य की आकस्मिकताओं का मूल्यांकन करने के लिए कई कारकों को तराजू में रखना होगा।

5. सुसम्मा थॉमस का मामला 1939 अधिनियम से उत्पन्न हुआ और अपील का फैसला 6 जनवरी, 1993 को इस न्यायालय द्वारा किया गया। 1939 अधिनियम मोटर वाहन अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया। 1988 (संक्षेप में, 1988 अधिनियम)। सुसम्मा थॉमस मामले में इस न्यायालय के फैसले के बाद, 1988 अधिनियम में संशोधन किया गया और, दलिया में, धारा 163 ए को दूसरी अनुसूची के साथ शामिल किया गया जो दिनांक 14 नवंबर, 1994 को प्रभावी हुआ, धारा 163 ए के तहत, संरचित फॉर्मूला आधार पर मुआवजे के भुगतान के संबंध में विशेष प्रावधान 1988 के अधिनियम में पेश किए गए थे और दूसरी अनुसूची में तीसरे पक्ष के घातक दुर्घटना/चोट के मामलों के दावों के लिए मुआवजे का प्रावधान किया गया था। दूसरी अनुसूची के तहत, अधिकतम गुणक 18 तक हो सकता है, न कि 16 जैसा कि सुसम्मा थॉमस में निर्धारित किया गया था। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य बनाम त्रिलोक चंद्र और अन्य,(1996) 4 एस सी सी 362 में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने वैधानिक प्रावधानों में बदलाव पर विचार किया, विशेष रूप से, 1988 के अधिनियम में धारा 163 ए और दूसरी अनुसूची

को शामिल करने पर विचार किया और इस प्रकार अवधारित कियाः

"17.1994 के संशोधन अधिनियम 54 द्वारा संशोधित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अधिनियमन के साथ स्थिति में अब बदलाव आया है। जहां तक मुआवजे के निर्धारण से संबंधित है, संशोधन द्वारा लाया गया सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है अध्याय ग्प् में धारा 163-ए और 163-बी का शीर्षक है "तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ मोटर वाहनों का बीमा" धारा 165-ए एक गैर-अस्थिर खंड से शुरू होती है और मृतक या घायल के कानूनी प्रतिनिधियों को, जैसा भी मामला हो, मुआवजे के भुगतान का प्रावधान करता है, जैसा कि दूसरी अनुसूची में दर्शाया गया है। अब यदि हम दूसरी अनुसूची की ओर रुख करते हैं, तो हमें एक तालिका मिलती है जो घातक दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले तीसरे पक्ष के दुर्घटना चोट के दावों के लिए मुआवजे की गणना के तरीके को तय करती है। पहला कॉलम दुर्घटना के पीड़ितों का आयु समूह बताता है, दूसरा कॉलम गुणक दर्शाता है और बाद के क्षैतिज आंकड़े मृतक पीड़ित के उत्तराधिकारियों को देय मुआवजे की मात्रा हजार में दर्शाते हैं। इस तालिका के अनुसार गुणक 5 से 18 तक भिन्न होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पीड़ित किस आयु वर्ग का है। इस प्रकार, इस अनुसूची के तहत अधिकतम गुणक 18 तक हो सकता है, न कि 16 जैसा कि सुसम्मा थॉमस मामले में अवधारित किया गया था।"

6. इस अपील में प्रस्तुत संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने 16 के गुणक के साथ पूंजीकृत गुणक के निर्धारण के बाद निर्धारित मुआवजे को 1/3 कम करने में गलती की थी। लेकिन उपरोक्त प्रश्न पर जाने से पहले, हम इस कोर्ट के हाल के दो फैसले, अर्थात, (1) सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य, बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य(2009) 6 एस सी सी 121. और (2) रेशमा कुमारी एवं अन्य बनाम मदन मोहन और अन्य (2009) 13 एस सी सी 422 पर ध्यान देगें। सरला वर्मा के मामले में(2009) 6 एस सी सी 121., इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने सुसम्मा थॉमस 2 और त्रिलोक चंद्र(1996) 4 एस सी सी 362; पर विचार किया; कुछ अन्य निर्णय, अर्थात अबाती बेजबरुआ बनाम भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण(2003) 2 एस सी सी 148.; फकीरप्पा और अन्य बनाम वी. कर्नाटक सीमेंट पाइप फैक्ट्री और अन्य(2004) 2 एस सी सी 473; टी.एन. राज्य परिवहन निगम लिमिटेड बनाम एस राजप्रिया और अन्य(2005) 6 एस सी सी 236.; न्यू इण्डिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम चार्ली एंड अन्य (2005) 10 एस सी सी 720, यूपी स्टेट रोड परिवहन निगम. बनाम कृष्णा बाला और अन्य(2006) 6एस सी सी 249., और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मीना वरियाल और अन्य (2007) 5 एस सी सी 428; और दो अंग्रेजी निर्णय भी - अर्थात, डेविस और अन्य बनाम वी. पॉवेल डफ़्रिन एसोसिएटेड कोलियरीज लिमिटेड (1942) 1 एआइआइ इआर 657;और नेंस बनाम ब्रिटिश कोलंबिया

इलेक्ट्रिक रेलवे कंपनी लिमिटेड (1951) 2 एआइआइ इआर 448; और मृत्यु के मामलों में मुआवजे के निर्धारण के संबंध में कुछ सिद्धांत निर्धारित किए । भविष्य की संभावनाओं के पहलू से निपटते समय, रिपोर्ट के पैराग्राफ 24 में, यह इस प्रकार कहा गया था-

> "सुसम्मा थॉमस (1994) 2 एससीसी 176, में इस न्यायालय ने आय में लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि की। सरला दीक्षित [(1996) 3 एससीसी 176] में आय में केवल 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई और अबाती बेजबरुआ में (2003) 2 एससीसी 148, आय में मात्र 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। असंभवताओं और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, हम एक सामान्य नियम अपनाने के पक्ष में हैं, मृतक की वास्तविक वेतन आय में वास्तविक वेतन का 50 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़ने के पक्ष में हैं। भविष्य की संभावनाएं, जहां मृतक के पास स्थायी नौकरी थी और उसकी उम्र 40 वर्ष से कम थी। (जहां वार्षिक आय कर योग्य सीमा में है, वहां "वास्तविक वेतन" शब्द को वास्तविक वेतन कम कर" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए)। जोड़ केवल होना चाहिए यदि मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष थी तो 30 प्रतिशत जहां मृतक की आयु 50 वर्ष से अधिक है, वहां कोई जोड़ नहीं

होना चाहिए। हालांकि साक्ष्य वृद्धि के एक अलग प्रतिशत का संकेत दे सकते हैं, लेकिन इसे मानकीकृत करना आवश्यक है अलग-अलग मापदण्डों को लागू करने या गणना के विभिन्न तरीकों को अपनाने से बचने के लिए। जहां मृतक स्व-रोज़गार में था या एक निश्चित वेतन पर था (वार्षिक वेतन वृद्धि आदि के प्रावधान के बिना), अदालतें आमतौर पर केवल वास्तविक पर ही विचार करेंगी मृत्यु के समय आय, बाहर से प्रस्थान केवल विशेष परिस्थितियों वाले दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए"

व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती के संबंध में कोर्ट ने इस प्रकार कहा;

"हालाँकि कुछ मामलों में व्यक्तिगत और व्यावसायिक खर्चों के लिए की जाने वाली कटौती की गणना त्रिलोक चांडी 1996) 4 एससीसी 362 में दर्शाई गई इकाइयों के आधार पर की जाती है, सामान्य अभ्यास मानकीकृत कटौती लागू करना है। इस न्यायालय के बाद के कई निर्णयों पर विचार करने के बाद, हम इस विचार के है कि जहां मृतक का इलाज किया गया था, वहां मृतक के व्यक्तिगत और जीवन-यापन के खर्चों के लिए कटौती एक तिहाई (1/3) होनी चाहिए, जहां आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या 2 से 3

है, एक-चौथाई (1/4) होनी चाहिए।जहां आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या 4 से 6 है, और एक-पांचवां (1/5 वां) जहां आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या छह से अधिक है।"

अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत आने वाले मामलों में गुणक के संबंध में, इस न्यायालय ने माना कि डेविस 12 का तरीका लागू होगा और निम्नलिखित तालिका निर्धारित की है:

मृतक की उम्र	सुसम्मा थॉमस में परिकल्पित गुणक स्केल	त्रिलोक चंद्र द्वारा अपनाया गया गुणक पैमाना	त्रिलोक चंद्र में गुणक पैमाना जैसा कि चार्ली में स्पष्ट किया गया है	एमवी अधिनियम की दूसरी अनुसूची की तालिका में दूसरे कॉलम में गुणक निर्दिष्ट है	मल्टीप्लायर वास्तव में एमवी अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उपयोग किया जाता है (जैसा कि मुआवजे की मात्रा से

					देखा जाता है)
1	2	3	4	5	6
15 वर्ष तक	-	-	-	15	20
15 से 20 वर्ष	16	18	18	16	19
21 से 25 वर्ष	15	17	18	17	18
26 से 30 वर्ष	14	16	17	18	17
31 से 35 वर्ष	13	15	16	17	16
36 से 40 वर्ष	12	14	15	16	15
41 से 45 वर्ष	11	13	14	15	14
46 से 50 वर्ष	10	12	13	13	12
51 से 55 वर्ष	9	11	11	11	10
56 से 60 वर्ष	8	10	9	8	8
61 से 65 वर्ष	6	8	7	5	6
65 वर्ष से ऊपर	5	5	5	5	5

उपरोक्त तालिका स्थापित करने के बाद, इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा -

"न्यायाधिकरण/अदालतें अलग-अलग ऑपरेटिव मल्टीप्लायरों को अपनाती हैं और लागू करती हैं। कुछ सुसम्मा थॉमस (1994) 2 एससीसी 176, उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) में निर्धारित, के संदर्भ में गुणक का पालन करते हैं; कुछ त्रिलोक के संदर्भ में गुणक का पालन करते हैं। (1996) 4 एससीसी 362,। उपरोक्त तालिका के कॉलम (3) में दिया गया है,; कुछ चार्ली के संदर्भ में गुणक का पालन करते हैं (2005) 10 एससीसी 720, कॉलम (4) में दिया गया है उपरोक्त तालिका,; कई लोग एमवी अधिनियम की दूसरी अनुसूची में तालिका के दूसरे कॉलम में दिए गए गुणक का पालन करते हैं उपरोक्त तालिका के कॉलम (5) में निकाला गया; और कुछ गणना करते समय वास्तव में दूसरी अनुसूची में अपनाए गए गुणक का पालन करते हैं मुआवजे की मात्रा उपरोक्त तालिका के कॉलम (6) में निर्धारित है)। उदाहरण के लिए यदि मृतक की आयु 38 वर्ष है, सुसम्मा थॉमस के अनुसार गुणक 12, त्रिलोक चंद्र के

अनुसार 14, चार्ली के अनुसार 15, या एमवी अधिनियम की दूसरी अनुसूची के कॉलम (2) में दिए गए गुणक के अनुसार 16 या गुणक के अनुसार 15 होगा। वास्तव में एमवी अधिनियम की दूसरी अनुसूची में अपनाया गया कुछ न्यायाधिकरण, इस मामले में, सेवानिवृत्ति की आयु के संदर्भ में सेवा के शेष वर्षों को लेते हुए 22 के गुणक को लागू करते हैं। इस प्रकार की विसंगति से बचना आवश्यक है। हम धारा 166 के तहत आने वाले मामलों से चिंतित हैं, न कि एमवी अधिनियम की धारा 163-ए के तहत। एमवी अधिनियम की धारा 166 के तहत आने वाले मामलों में डेविस विधि लागू है।"

इसलिए हमारा मानना है कि उपयोग किए जाने वाले गुणक को ऊपर दी गई तालिका के कॉलम (4) में उल्लिखित होना चाहिए (सुसम्मा थॉमस, त्रिलोक चंद्र और चार्ली को लागू करके तैयार किया गया है), जो 18 (के लिए) आयु समूहों के ऑपरेटिव गुणक से शुरू होता है। 15 से 20 और 21 से 25 साल), हर पांच साल में एक यूनिट कम हो जाती है, यानी 26 से 30 वर्ष के लिए एम-17। 31 से 35 वर्ष के लिए एम-16, 36 से 40 वर्ष के लिए एम-15। 41 से 45 वर्ष के लिए एम-14, और 46 से 50 वर्ष के लिए एम-13, फिर हर पांच साल के लिए दो यूनिट कम कर दी जाती

है, यानी 51 से 55 वर्ष के लिए एम-11, 56 से 60 वर्ष के लिए एम-9, 61 से 65 वर्ष के लिए एम-7 और 66 से 70 वर्षो के लिए एम-5"

7. रेशमा कुमारी में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीश पीठ ने फिर से भारतीय और अंग्रेजी मामलों की एक लंबी श्रृंखला देखी, जिनमें से अधिकांश जो सरला वर्मा में देखे गए थे (लेकिन सरला वर्मा पर ध्यान नहीं दिया गया था) और विचलन को देखते हुए इस सवाल पर राय कि क्या दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट गुणक को 1988 अधिनियम की धारा 166 के तहत आने वाले मामले में देय मुआवजे की राशि की गणना के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में लिया जाना चाहिए, ने मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया।

8. मुद्दा यह है कि क्या अधिनियम 1988 की धारा 163ए के प्रयोजनों के लिए दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट गुणक के अंतर्गत आने वाले मोटर दुर्घटना दावा मामले में मुआवजे की राशि की गणना के लिए मार्गदर्शक माना जा सकता है। अधिनियम 1988 की धारा 166 पर अभी तक आधिकारिक रूप से निर्णय नहीं लिया गया है और यह बड़ी पीठ के समक्ष विचाराधीन है। जहां तक वर्तमान अपील का सवाल है, यह अधिनियम 1939 की धारा 110-ए के तहत दायर एक मोटर दुर्घटना दावे से उत्पन्न हुई है और इसलिए, दूसरी अनुसूची जो अधिनियम 1988 की धारा 163 ए को संदर्भित करती है, वह ज्यादा मार्गदर्शन नहीं कर सकती

है। ऊपर बताए गए प्रश्न पर लौटते हुए, यह तुरंत कहा जाना चाहिए कि दुर्घटना के समय मृतक यूपी सरकार के सिंचाई विभाग में नौकरी कर चुका था। वह कार्यकारी अभियंता के रूप में कार्य कर रहे थे और उनके पास समय के साथ कार्यकारी अभियंता और अधीक्षण अभियंता के पद पर नियमित पदोन्नति का उचित मौका था; सेवानिवृत्ति से पहले उनकी लगभग 18 वर्ष की सेवा शेष थी। 18 वर्ष की इस अवधि के दौरान उन्हें पदोन्नति के अलावा वार्षिक वेतन वृद्धि आदि भी मिलती। लेकिन जीवन के उतार-चढ़ाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, हो सकता है कि वह उस उम्र तक जीवित न रहे हों; हो सकता है कि उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो। किसी घातक दुर्घटना के मामले में, मृत्यु की तारीख के बाद मृतक के साथ जो कुछ भी हुआ होगा वह अनिश्चित रहता है। दुर्घटना के समय उनका सकल वेतन रु. 2680/-, उनके अंतिम वेतन प्रमाण पत्र से परिलक्षित होता है। उन्नति और भविष्य के करियर की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने मृतक की आय अंतिम सकल वेतन को दोगुना करके और इसे एक राउंड फिगर बनाकर 5400/- रूपये प्रति माह मानी। तब उच्च न्यायालय ने उनके व्यक्तिगत व्यय के लिए एक तिहाई राशि काट ली और रुपये के आंकड़े पर पहुंचे। मृतक द्वारा परिवार को अपेक्षित योगदान के रूप में 3600/- प्रति माह और 16 के गुणक को लागू करने पर निर्भरता का आकलन रुपये पर किया गया। 6,91,200/- लेकिन, हालांकि, जीवन की असंभवता और अनिश्चितता को ध्यान में रखते

हुए 1/3 की और कटौती की गई और इस तरह मुआवजे के रूप में केवल 4,70,000/- रु. की राशि प्रदान की गई। हमने देखा है कि सुसम्मा थॉमस 2 में दुर्घटना के समय मृतक की आय में 100 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान मृतक की सकल आय के रूप में लगाया गया था। दूसरी ओर, सरला वर्मा में इस न्यायालय ने सामान्य नियम निर्धारित किया, यानी, भविष्य की संभावनाओं के लिए 50 प्रतिशत अतिरिक्त, जहां मृतक के पास स्थायी नौकरी थी और 40 वर्ष से कम था के लिए की जाने वाली कटौती के संबंध में व्यक्तिगत व्यय, सरला वर्मा मामले में इस न्यायालय ने कहा कि जहां मृतक विवाहित था और जहां आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या 4 से 6 है, वहां सकल आय का 1/4 हिस्सा काटा जाना चाहिए, जबकि सुसम्मा थॉमस में, पारंपरिक 1/3 किसी भी सबूत के अभाव में सकल आय का तीसरा हिस्सा उस हिसाब से काट लिया गया था। फिर सरला वर्मा में तालिका सेट बी के अनुसार यदि मृतक की आयु 36 से 40 वर्ष है, तो 15 का गुणक लागू होता है, जबकि सुसम्मा थॉमस 2 में निर्भरता की हानि को 12 के गुणक पर पूंजीकृत किया गया था (मृतक की आयु 39 वर्ष थी) . प्रश्न यह है कि क्या इस अपील में निर्भरता के मूल्य की पुनर्गणना की जानी चाहिए। हम ऐसा नहीं सोचते. उच्च न्यायालय ने गुणक या दूसरे शब्दों में रुपये पर निर्भरता का मूल्य निर्धारित किया। सुसम्मा थॉमस में इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए 3600/- प्रति माह हमारी राय में, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत

अधिकार क्षेत्र में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों को लागू करके समय की इस दूरी पर गुणक की पुनर्गणना करना न तो उचित है और न ही वांछनीय है। सरला वर्मा उच्च न्यायालय ने सुसम्मा थॉमस मामले में दिए गए कई दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा है, जो हमारे विचार में पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, हम सोचते हैं कि 16 के गुणक पर गुणक का पूंजीकरण उच्चतर पक्ष पर है और मामले के तथ्यों में 14 का गुणक न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा, इस तरह, अपीलकर्ता रुपये के हकदार बन जाते हैं। 6,04,800/- मुआवज़े के रूप में, जो हमारी राय में, उचित और न्यायसंगत है। हालाँकि, बंद करने से पहले, इसे आयोजित करना होगा और हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने एक विशेष गुणक पर पूंजीकृत गुणक के निर्धारण के बाद निर्धारित मुआवजे को 1/3 कम करने में स्पष्ट रूप से गलती की थी, क्योंकि गुणक के निर्धारण की विधि ही इसमें शामिल है। अपरिहार्य कारकों और भविष्य की आकस्मिकताओं पर विचार करें। एक बार जब गुणक और गुणक का पता चल जाता है, तो आश्रितों की क्षतिपूर्ति के लिए नुकसान का आकलन दोनों को गुणा करके निकाला जाता है और अनिश्चितताओं और अन्य आकस्मिकताओं के लिए कोई और कटौती करने की आवश्यकता नहीं होती है।

9. परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा रुपये 4,70,000/- को बढ़ाकर रु. 6,04,800/-की

राशि का मुआवजा दिया जाता है। अपीलकर्ता दावा याचिका दायर करने की तारीख से उसके वास्तविक भुगतान की तारीख तक बढ़ी हुई राशि पर प्रति वर्ष 9 प्रतिशत साधारण ब्याज के भी हकदार होंगे। पक्षकारान खर्चा मुकदमा स्वयं वहन करेगें।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री महेंद्र कुमार दवे (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्य के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।